

सम्पादकीय

ऐक्या में स्मार्टफोन के प्रचलन से एकाग्रता एवं हेल्थ रखते में

शिक्षा में तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन के उपयोग और उसके घाटक प्रभावों को लेकर दुनियाभर में हलचल है, बड़े शोध एवं अनुसंधान हो रहे हैं, जिनके निष्कर्षों एवं परिणाम को देखते हुए कड़े कदम भी उठाये जा रहे हैं। शोध एवं अध्ययनों के तथ्यों ने चौंकाया भी है एवं चिन्ता में भी डाला है। पाया गया कि जो छात्र अपने फोन के करीब रहकर पढ़ाई करते हैं, उन्हें ध्यान केंद्रित करने में बहुत मुश्किल होती है, भले ही वे इसका उपयोग न कर रहे हों। स्मार्टफोन के उपयोग से नींद की गुणवत्ता कम होने, तनाव बढ़ने, एकाग्रता बाधित होने, स्मृति लोप होने, अवांछित सामग्री का अधिक उपयोग करने, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ने जैसे खतरे उभरें हैं। इन बढ़ते खतरों को देखते हुए दुनियाभर में कम से कम 79 शिक्षा प्रणालियों ने स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसे लेकर, कई देशों में बच्चों की शिक्षा और निजता पर इसके प्रभाव को लेकर बहस जारी है। 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' (यूनेस्को) की वैश्विक शिक्षा निगरानी (जीईएम) टीम के अनुसार, 60 शिक्षा प्रणालियों या वैश्विक स्तर पर प्रत्येकीकृत कुल शिक्षा प्रणालियों का 30 प्रतिशत ने विशेष कानूनों या नीतियों के माध्यम से 2023 के अंत तक स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में अभी इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। सर्वेक्षण के अंकिते यह संकेत देते हैं कि डिजिटल शिक्षा और स्मार्टफोन के इस्तेमाल में बच्चों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। यह बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहा है, लेकिन साथ ही इसके साथ कई चुनौतियाँ भी हैं, डिजिटल शिक्षा को संतुलित और सुरक्षित बनाना आने वाले समय में एक प्रमुख चुनौती है। डिजिटल शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के साथ, यह आवश्यक हो गया है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट का सही, संयमपूर्ण और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। ताकि बच्चों का विकास सही दिशा में एवं समग्रता से हो। निस्संदेह, शिक्षा के बाजारीकरण और नए शैक्षिक प्रयोगों में मोबाइल की अपेक्षाओं को महंगे स्कूलों ने स्टेट्स सिंबल बना दिया है। लेकिन हालिया वैश्विक सर्वेक्षण बता रहे हैं कि पढ़ाई में अत्यधिक मोबाइल का प्रयोग विद्यार्थियों के लिये मानसिक व शारीरिक समस्याएं पैदा कर रहा है। सर्वविदित है कि विभिन्न ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रमों के चलते छात्र-छात्राओं में मोबाइल फोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। तमाम पब्लिक स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल अनिवार्य तक बना दिया है। कमोबेश सरकारी स्कूलों में ऐसी बाध्यता नहीं है। लेकिन वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि स्मार्टफोन एक हद तक तो सोखने की प्रक्रिया में मददगार साबित हुआ है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने से पढ़ाई में बाधा आती है, नैसर्गिक शैक्षणिक गुणवत्ता आहत होती है।

भारत में 21 राज्यों के ग्रामीण समुदायों में 6-16 वर्ष का आयु के स्कूली बच्चों के 6,229 अधिभावकों के बीच किए गए अखिल भारतीय सर्वेक्षण से पता चला कि अधिकतर बच्चे पढ़ाई के बजाय मनोरंजन एवं अश्लील सामग्री के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि जिन छात्रों के पास गैजेट्स हैं, उनमें से 56.6 प्रतिशत ने डिवाइस का इस्तेमाल मूरी डाउनलोड करने और देखने के लिए किया, जबकि 47.3 प्रतिशत ने उनका इस्तेमाल संगीत डाउनलोड करने और सुनने के लिए किया। सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्रामीण भारत में 49.3 प्रतिशत छात्रों के पास स्मार्टफोन की पहुंच है, लेकिन उनमें से केवल 34 प्रतिशत ही पढ़ाई के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वैश्विक स्तर पर, आज दुनिया भर में 6.378 बिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं—जो कि कुल आबादी का लगभग 80.69 प्रतिशत है। इसमें दो मत नहीं कि एक समय महज बातचीत का जरिया माना जाने वाला मोबाइल फोन आज दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने वाला बेहद जरूरी उपकरण बन चुका है। खासक कोरोना संकट के चलते स्कूल-कालेजों के बंद होने के बाद तो यह पढ़ाई का अनिवार्य हिस्सा बन गया। आलालाइन कक्षाओं के बढ़ते प्रचलन में लाग्ने लगा था कि इसके बिना तो पढ़ाई संभव ही नहीं है। लेकिन नादान बच्चों के हाथ में मोबाइल बंदर के हाथ में उस्तरे जैसा ही साबित हुआ है। निश्चित तौर पर ये उनके भटकाव, गुमराह, दिग्ध्रमित और मानसिक विचलन का कारण भी बना है। इसी कारण कई देशों में स्कूलों में स्मार्टफोन पर बैन लगा दिया है, क्योंकि इन देशों का मानना है कि यह बच्चों की शिक्षा और उनकी गोपनीयता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अनेक देशों में हुए सर्वेक्षणों ने स्मार्टफोन के उपयोग से विद्यार्थियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर चिंता जतायी है। इनकी रिपोर्ट एवं चौंकाने वाले तथ्य भारत में शिक्षा के नीति-नियंत्रणों की आंख खोलने वाले हैं। यूनेस्को की टीम के मुताबिक बीते साल के अंत तक कुल पंजीकृत शिक्षा प्रणालियों में से चालीस फीसदी ने सख्त कानून या नीति बनाकर स्कूलों में छात्रों के स्मार्टफोन के प्रयोग पर रोक लगा दी है। दरअसल, आधुनिक शिक्षा के साथ आधुनिकीकरण एवं विकास की अपेक्षा को दर्शा कर तमाम पब्लिक स्कूलों में मोबाइल के उपयोग को अनिवार्य बना दिया गया। निस्संदेह, आधुनिक समय में स्मार्टफोन कई तरह से शिक्षा में मददगार है। लेकिन यहां प्रश्न इसके अनियंत्रित एवं वर्वांछित प्रयोग का है।

बाग्या के लाल विष्णु देव का कमालः छत्तीसगढ़ में ट्रिपल हुंजन का सरकार

सरकार है। यह संभव हो सका है प्रदेश के गृहस्थी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और सुशासन से। भैषजाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उन्होंने संवेदनशीलता के साथ हर वर्ग का ध्यान रखकर नीतियां बनायी। परिणाम सबके सामने है। साय सरकार के 14 महीने की अल्पावधि में ही चूहोंसे सांघर्ष काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जीतने में विष्णु देव साय कामयाब हुए। नीतीजतन, हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का सूपड़ा साफ़ हो गया। विधानसभा, लोकसभा के बाद अब नगरीय निकायों के चुनाव में भारी सफलता ने विष्णु देव के कुशल नेतृत्व पर मुहर लगा दी है। निश्चय ही ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से अब छत्तीसगढ़ में विकास की गति तेज होगी। दूसर्य आदिवासी अंचल जशपुर के बगिया गांव में विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को हुआ। तब किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि बगिया का यह लाल, एक दिन छत्तीसगढ़ के मुरियांवाड़ी की महत्वी जिम्मेदारी संभालेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्विवाद आदिवासी मुख्यमंत्री होने का इतिहास विष्णुदेव साय के नाम पर दर्ज है। उनके सहज, सरल

भाव साफ झलकता है। मृदुभाषी होने के साथ ही प्रशासनिक कसावट को लेकर उनकी छिप ने जन सामाज्य का दिल जीत लिया है। वैसे तो पंच से लेकर सरपंच, विधायक, सांसद, केंद्रीय राज्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनव



तक का उनका राजनीतिक सफर उपलब्धिर
भरा है। लेकिन, बीते 14 महीने में मुख्यमंत्री
के रूप में उनके द्वारा बनाई गई जनतिष्ठी
नीतियों से सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिल

किसानों के दुख-दर्द को भलीभांति जानते
और समझते हैं। अन्नदाता किसानों की चिंता
करते हुए विष्णु देव साथ ने सरकार बनते
सबसे पहले किसानों का दो साल का बक्का
बोनस दिया। 3100 रुपये प्रति वर्षटिल कर्म

वकुमार, अजय राय, सच्चन चुके हैं। यूपी में समाजवादी तत अभियान ही चला दिया है। ५५ हम विरोधी दल हैं हमारा तो रना है। तो सरकार पर सबाल सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जा रहा है।

पी करने के लिए सपा सांसद भाइ है क्योंकि उन्होंने कहा था हाउसफ्ल हो जायगा। उत्तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताने वालों को सटीक और भा में कहा कि सनातन का तो ये अपराध मेरी सरकार ने बयान में सपा पर हमलावार खें तो वहां की भाषा उनके सी सभ्य समाज की नहीं हो ते थे लेकिन अक्षयवट और ज्ञान का स्तर है। मुख्यमंत्री ने ऐ भूखा नहीं रहा, महाकुंभ में उठाय जा रहे सभा सवालों का जवाब देते हुए कहा एक संगम का पाना केवल नहाने के लिए अपितु आचमन के लिए भी उपयुक्त है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि संगम व महाकुंभ को बदनाम करने के लिए लगातार झूट अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संगम और उसके आसपास के सभी पाइप और नलों को टेप कर दिया गया है और पानी का शुद्ध करने के बाद ही छोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पानी की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। आज कंपनी रिपोर्ट के अनुसार संगम के पास बीओडी की मात्रा ३ से कम है और घुलिया ऑक्सीजन ८-९ के आसपास है। इसका तात्पर्य यह है कि संगम का पानी न केवल नहाने के लिए अपितु आचमन के लिए भी उपयुक्त है। हिंदू विरोध इंडी गढ़बंधन के नेताओं की हिंदू आस्था पर आघात करने की आदत बढ़ चुकी है। यह सभी दल हीन भावना से ग्रसित हो चुके हैं इन्हें हिंदू समाज का उत्थान, हिंदू समाज का वैभव परसंद नहीं आ रहा है, जाग्रत, एकता से युक्त एकरस हिंदू समाज इनको परसंद नहीं आ रहा है इन सभी दलों को मां गंगा की अविरल धारा में अपनी राजनीति समाप्त होती नजर आ रहा है जिसका कारण यह सभी एक स्वर में महाकुंभ को मृत्युकुंभ बताने लग गये हैं वास्तविकता यह है कि समरसता के इस समागम में सनातन संस्कृति साकार हो रही है आम हिंदू जन पहली बुद्धिकी शुचिता की, दूसरी भक्ति की और तीसरी ज्ञान की लगा रहे हैं। यह महाकुंभ- २०२५ और संगम एकता प्रेम, त्याग तपस्या का प्रतीक बन चुका है।

के नीचे नहीं सोएगा, सबका खुद का आशियाना होगा, इसकी चिंता करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 18 लाख से अधिक जरूरतमंद हिंदूहियों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मुख्यमंत्री बनते ही दी। यह उनकी संवेदनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी तरह माता-बहु को स्वावलंबी बनाने की दिशा में महत्वारी वंदन योजना मील का पत्थर साबित हो रहा है। महीने करीब 70 लाख महिलाओं के रहने में सीधा एक हजार रुपये जमा होने से उन जीवन स्तर में बहुत कुछ बदलाव आया है। माताएं-बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं। युवाओं विद्यास सरकारी व्यवस्था पर से उठने लगा पूर्ववर्ती सरकार में पीएससी में हुए बड़े पैमाण पर योटाले की वजह से युवा खुद को ठांगा हुआ महसूस कर रहे थे। युवा, किसी भी देश राज्य के भविष्य की रीढ़ हैं। पीएससी परीक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन और पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं आयोजित होने वालों का भरोसा जीतने में विष्णु देव साय का मयाब हुए हैं। उत्तीसांगड़ की औद्योगिक नीति को लोकव्यापी और सुगम बनाकर इन्वेस्टर को आकर्षित करने में विष्णु देव साय का मयाब हुए हैं। विकासशील छत्तीसगढ़

विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में साथ सरकार के नई औद्योगिक नीति निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी। धर्म-कर्म-अध्यात्म, सनातन की रीढ़ हैं। चाहे राजिम कुंभ कल्प को पुर्वप्रतिष्ठित करने की बात हो, या प्रयागराज महाकुंभ में उत्तीसगढ़ पवेलियन बनाकर श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया कराने की बात अथवा श्रीराम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना से प्रदेश के 20 हजार से अधिक नागरिकों को अयोध्या धाम का दर्शन कराने की बात हो, विष्णु देव ने देवतुल्य जनता का बरबूनी रखाया रखा है। सुशासन समष्टि छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साथ की नीतियां जन-जन के लिए कल्याणकारी और उपयोगी साबित हुई हैं। लोकतंत्र में जनता के मंशानुरूप और उनके भरोसे को कायम रखकर काम करना कुशल नेतृत्व का परिचायक है। एक के बाद एक लगातार लोकसभा और नगरीय निकाय में मिला बड़ा जनादेश विष्णु देव साथ की कुशल रणनीति, साफ नीतियाँ और पारदर्शी शासन व्यवस्था का ही परिणाम है। इन दिनों हाँ जुबां पर एक ही चर्चा है— सुशासन के दम पर बगिया के लाल विष्णु देव ने कर दिया कमाल।

